

**राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा प्रस्तावित (वर्ष 2017–18 की) प्रत्येक योजना के
सम्बन्ध में सूचना (आउटकम बजट)**

(आउट ले की धनराशि रु० हजार में)

योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
1	2	3	4	5	6	7

राजस्व

लेखाशीर्षक—2052 सचिवालय सामान्य सेवा, 091—संलग्न कार्यालय—03—राज्य सम्पत्ति विभाग	राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत अधिष्ठान एवं उससे सम्बन्धित क्रियाकलापों की पूर्ति करना।	3,33,934	अधिष्ठान के अन्तर्गत कुल 378 कार्मिकों के वेतन आदि का भुगतान।	—	शासकीय कार्यों के सुचारू संचालन हेतु मानव संसाधनों एवं अन्य क्रियाकलापों की पूर्ति।	—
0301—सामान्य मरम्मत 29—अनुरक्षण	राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत आवासीय/अनावासीय भवन में छुट—पुट अनुरक्षण/मरम्मत कार्य कराया जाना।	8,000	देहरादून स्थित मुख्यमंत्री एवं मंत्री आवासों सहित कुल 1155 शासकीय आवासों एवं विभिन्न स्थानों पर अवस्थित 11 अतिथि गृहों में आवश्यक अनुरक्षण/मरम्मत कार्य कराया जाना।	—	आवासीय/अनावासीय भवनों को दुरुस्त रखे जाने हेतु समय—समय पर आवश्यक अनुरक्षण/ मरम्मत कार्य।	—
03—गैरसैण में आयोजित विधान सभा सत्र के प्रकीर्ण व्ययों हेतु बजट व्यवस्था 42—अन्य व्यय	समय पर गैरसैण में आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान होने वाले प्रकीर्ण कार्यों हेतु बजट व्यवस्था किया जाना।	2,000	विधानसभा सत्र के दौरान संवैधानिक पदधारकों, विशिष्ट महानुभवों एवं उच्चाधिकारियों के ठहरने, भोजन, जलपान, वाहन एवं अन्य व्यवस्थायें सुनिश्चित करना।	—	विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न आवश्यक शासकीय व्यवस्थायें सुनिश्चित करना।	—

पूँजीगत

योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
1	2	3	4	5	6	7
लेखाशीर्षक 4216—आवास पर पूँजीगत	राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन	30,000	राजधानी देहरादून में कार्यरत अधिकारियों/	—	उत्तराखण्ड राज्य की राजधानी देहरादून में कार्मिकों की आवासीय व्यवस्था हेतु यमुना	—

परिव्यय-02-शहरी आवास-800-अन्य भवन-03-राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण 24-वृहत् निर्माण	आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण/आशिक निर्माण कार्य।		कर्मचारियों के लिये नये आवासीय भवनों का निर्माण एवं कार्मिकों हेतु विभिन्न कम्युनिटी हॉल, बैडमिंटन कोर्ट जैसे अन्य भवन संरचनायें निर्मित किया जाना।	कॉलोनी में श्रेणी-4 के बहुमंजिले आवासीय भवन का निर्माण कार्य का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।	
04-उत्तराखण्ड निवास, नई दिल्ली का विस्तार, जीर्णोद्धार आदि 24-वृहत् निर्माण	वर्तमान में उत्तराखण्ड निवास, नई दिल्ली का ध्वस्तीकरण कर नये अतिथि गृह का निर्माण प्रस्तावित है।	1	-	-	-
11-मसूरी में राज्य अतिथि गृह हेतु राधा भवन इस्टेट का अधिग्रहण 24-वृहत् निर्माण	राज्य के अत्यन्त महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल पर राज्य अतिथि गृह विकसित किया जाना।	1	संवैधानिक पदधारकों, विशिष्ट महानुभवों एवं उच्चाधिकारियों के साथ-साथ देश के विभिन्न स्थानों से आने वाले पर्यटकों को सस्ती एवं सुलभ अवस्थान सुविधा उपलब्ध कराया जाना।	-	-
12-मुम्बई में उत्तराखण्ड भवन एवं इम्पोरियम की स्थापना 24-वृहत् निर्माण कार्य	उत्तराखण्ड राज्य की सांस्कृति परम्पराओं एवं पर्यटन को भारत के मध्य, पश्चिम एवं दक्षिण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार एवं संवैधानिक पदधारकों, विशिष्ट महानुभवों एवं उच्चाधिकारियों को राष्ट्र की वित्तीय राजधानी मुम्बई प्रवास के दौरान उनके गरिमामय अवस्थान एवं वाणिज्य प्राप्ति के स्रोत के रूप में विकसित किया जाना।	1,00,000	राष्ट्र की वित्तीय राजधानी मुम्बई प्रवास के दौरान विशिष्ट/अति विशिष्ट महानुभवों गरिमामय अवस्थान एवं वाणिज्य प्राप्ति के स्रोत के रूप में विकसित किया जाना।	प्रश्नगत निर्माण कार्य का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।	2017
13-मुख्य सचिव स्तर के आवासीय भवनों का निर्माण 24-वृहत् निर्माण कार्य	उत्तराखण्ड शासन में कार्यरत मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को उनकी गरिमा के अनुरूप राजधानी देहरादून में आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना।	28,000	शासन में कार्यरत मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव एवं अन्य उच्चाधिकारियों को आवासीय सुविधा प्रदान करना।	प्रश्नगत निर्माण कार्य का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।	2017

14—उत्तराखण्ड निवास (नई दिल्ली) का ध्वस्तीकरण के पश्चात नवीन भवन का निर्माण। 24—वृहत् निर्माण कार्य	राष्ट्र की राजधानी में संवैधानिक पदधारकों, विशिष्ट महानुभवों एवं उच्चाधिकारियों की अवस्थान व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना।	1	राष्ट्र की राजधानी में दिल्ली पधारने वाले राज्य के संवैधानिक पदधारकों, विशिष्ट महानुभवों एवं उच्चाधिकारियों को आवासन सुविधा प्रदान किया जाना।	कार्यदायी संस्था से आगणन प्राप्त हो चुका है, जिसका परीक्षण टी००५०००० द्वारा किया जा रहा है।	2018
15—राज्य अतिथि गृह नैनीताल का जीर्णोद्धार। 24—वृहत् निर्माण कार्य	राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल एवं मा० उच्च न्यायालय स्थापित होने के दृष्टिगत नैनीताल में संवैधानिक पदधारकों, विशिष्ट महानुभवों एवं उच्चाधिकारियों का निरन्तर आवागमन होने के फलस्वरूप अतिथि गृह की आवश्यकता के अनुसार समय—समय पर जीर्णोद्धार के कार्य कराया जाना।	5,000	—	—	—
16—रुद्रप्रयाग एवं हरिद्वार में राज्य अतिथि गृहों का निर्माण। 24—वृहत् निर्माण कार्य	राज्य के चारधाम यात्रा मार्ग पर अवस्थित महत्वपूर्ण पड़ाव रुद्रप्रयाग में	5,000	चारधाम यात्रा मार्ग के महत्वपूर्ण पड़ाव रुद्रप्रयाग में राज्य अतिथि गृह का	प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु चिह्नित भूमि का राज्य सम्पत्ति विभाग को हस्तांतरण हो चुका है।	2018
	संवैधानिक पदधारकों, विशिष्ट महानुभवों एवं उच्चाधिकारियों के आवागमन के दौरान उन्हें आवश्यक अवस्थान सुविधा प्रदान किया जाना।		निर्माण किया जाना।		
17—रायपुर (देहरादून) में सचिवालय भवन का निर्माण (फेज-1) (एस०पी०५०) 24—वृहत् निर्माण कार्य	सचिवालय एवं विधानसभा भवन किसी भी राज्य की सर्वोच्च संवैधानिक संस्थायें हैं। वर्तमान समय में उत्तराखण्ड राज्य सचिवालय एवं विधानसभा में पर्याप्त स्थान की अनुपलब्धता होने के दृष्टिगत रायपुर, देहरादून में नया विधानसभा भवन, सचिवालय भवन एवं अन्य अवस्थापना सम्बन्धी सुविधायें विकसित किया जाना।	1	राज्य के महत्वपूर्ण संस्थाओं सचिवालय एवं विधानसभा में पर्याप्त स्थान की अनुपलब्धता के दृष्टिगत नये विधानसभा भवन, सचिवालय एवं अन्य अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं का निर्माण।	उक्त कार्य हेतु अपेक्षित वन भूमि हस्तांतरण हेतु वन परामर्शीय समिति द्वारा सेंट्रलिक सहमति प्रदान कर दी गयी है।	2018
18—भराड़ीसैण (गैरसैण) चमोली में विधान सभा भवन एवं अन्य अवस्थापना सम्बन्धी निर्माण।(एस०पी०५०) 24—वृहत् निर्माण कार्य	वर्तमान में उक्त कार्य विधानसभा सचिवालय को हस्तांतरित हो चुका है।	1	—	—	—
19—जनपद चमोली के भराड़ीसैण (गैरसैण) में मिनी सचिवालय का निर्माण। 24—वृहत् निर्माण कार्य	राज्य की जनभावनाओं के अनुरूप पर्वतीय क्षेत्र के विकास एवं पर्यटन की अपार संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य की पर्वतीय राजधानी विकसित किये जाने के उद्देश्य से भराड़ीसैण (गैरसैण) में मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाना।	10,000	राज्य की जनभावनाओं के अनुरूप पर्वतीय क्षेत्र के विकास एवं पर्यटन की अपार संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य की पर्वतीय राजधानी विकसित किये जाने के उद्देश्य से भराड़ीसैण (गैरसैण) में मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाना।	निर्माण कार्य हेतु चिह्नित भूमि को पशुपालन विभाग से राज्य सम्पत्ति विभाग के नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।	2018